नवीन ऊर्जा में सरकारी कंपनियां करेंगी बड़ा निवेश

पेट्रोलियम उत्पादक ओएनजीसी और सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने हाथ मिलाया

जयप्रकाश रंजन ● जागरण

- कोल इंडिया वर्ष 2028 तक 5000 मेगावाट की क्षमता सौर ऊर्जा से हासिल करने की योजना पर कर रही काम
- सौर, पवन और दूसरी रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता में काफी वृद्धि के बावजूद भारत वर्ष 2030 के लक्ष्यों से दूर

नई दिल्ली: पिछले दिनों देश की ऊर्जा क्षेत्र की तीन दिग्गज कंपनियों ओएनजीसी, एनटीपीसी और कोल इंडिया (सीआइएल) ने रिन्यूएबल ऊर्जा सेक्टर को लेकर काफी अहम घोषणाएं की हैं। नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर के सौर, पवन व दूसरे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने के लिए देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम उत्पादक कंपनी ओएनजीसी और सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने हाथ मिलाया है। वहीं देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी सीआइएल ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाते हुए रिन्यूएबल सेक्टर में अपने विस्तार की बात स्वीकार की है। कोल इंडिया वर्ष 2028 तक पांच हजार मेगावाट की क्षमता सौर ऊर्जा से हासिल करने की योजना पर काम कर रही है। दरअसल, सभी सरकारी कंपनियों की तरफ से की गई घोषणाएं केंद्र सरकार की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हैं, जिसमें वह अपनी पारंपरिक ऊर्जा कंपनियों को कालांतर में रिन्यूएबल सेक्टर की बड़ी ऊर्जा कंपनी में बदलना चाहती है।

सरकार के लिए यह काम इसलिए भी जरूरी है कि भारत में सौर, पवन और दूसरी रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता में काफी इजाफा होने के बावजूद हम वर्ष 2030 के लक्ष्यों से काफी दूर हैं। हाल के महीनों में कई बाहरी एजेंसियां अपनी रिपोर्ट में इस बात की आशंका जता चुकी हैं अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो भारत के लिए, वर्ष 2030 तक रिन्यूएबल सेक्टर से पांच लाख मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा।

एक हफ्ते पहले ही नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने बताया था कि पिछले 10 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता में 396 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सितंबर, 2024 में यह 2.10लाख मेगावाट से ज्यादा हो गई है। सौर ऊर्जा के जरिये बिजली उत्पादन क्षमता 30 गुना बढ़कर 91 हजार मेगावाट के करीब हो गई है। इस हिसाब से अगले छह वर्षों में अतिरिक्त 2.90 लाख मेगावाट क्षमता जोड़नी है। यानी इस दौरान हर वर्ष 50 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़नी होगी। जबकि वर्ष 2023-24 में भारत ने सिर्फ 19 हजार मेगावाट क्षमता ही जोड़ने में सफलता हासिल की है।

आने वाले समय में सरकारी कंपनियों का होगा अलग महत्व

सूत्रों का कहना है कि अभी तक भारत के रिन्यूएबल ऊर्जा सेक्टर में निजी क्षेत्र की धमक थी, लेकिन आने वाले दो से तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र की ऊर्जा कंपनियों का अलग महत्व होगा। उदाहरण के तौर पर ओएनजीसी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश समेत कुछ दूसरे राज्यों में रिन्यूएबल ऊर्जा संयंत्र लगाने की कई संभावनाओं की समीक्षा कर रही है। इसमें सौर प्लांट से लेकर हाइब्रिड और छोटी पनबिजली परियोजनाएं शामिल हैं। अब कंपनी ने एनटीपीसी के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम बनाया है, जो सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर में नया निवेश करेगा। इन दोनों के गठबंधन की नजर अयाना रिन्यूएबल पावर पर है। दोनों कंपनियों की बराबर हिस्सेदारी (50:50) वाले संयुक्त उद्यम के गठन का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। जानकार बता रहे हैं कि इस अधिग्रहण के बाद भी यह संयुक्त उद्यम कुछ दूसरी रिन्यूएबल कंपनियों पर नजर रख रही है ताकि भविष्य में उनको खरीदा जा सके। एनटीपीसी पहले ही रिन्यूएबल सेक्टर में उतर चुकी है और इसके लिए स्थापित सब्सिडियर एनटीपीसी ग्रीन के जरिये यह वर्ष 2032 तक इस सौर, पवन व दूसरे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल 62 हजार मेगावाट बिजली क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।